**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

निर्णय की तिथि: 10 जनवरी, 2025

इस मामले में:

**सि.वा. (मू.प.) 63/2017**
**CS(OS) 63/2017**

श्री इंद्रजीत सिंह बिंद्रा .....वादी

द्वारा: श्री श्यामल कुमार, अधिवक्ता

बनाम

श्रीमती रमेश कुमारी व अन्य ..... प्रतिवादीगण

द्वारा: श्री ओंकारेश्वर कांडपाल, श्री प्रकाश चंद्र, अधिवक्तागण प्रतिवादी-1(क) हेतु।
श्री राजेश यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री वी. पी. राणा, श्री रजत अग्निहोत्री, श्री कुणाल मित्तल, सुश्री भावना, अधिवक्तागण डी-1(ख) हेतु ।

**कोरमः**
**माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभ्रमोणियम प्रसाद**

**निर्णय (मौखिक)**

**अंतर.आ. 545/2025**

1. यह पुनर्विलोकन याचिका दायर करने में देरी को माफ करने के लिए वादी की ओर से एक आवेदन है।

2. आवेदन में बताए गए कारणों के लिए, पुनर्विलोकन याचिका दायर करने में 18 दिनों की देरी को माफ किया जाता है।

3. आवेदन का निपटान किया जाता है।

**<u>पुनर्विलोकन याचिका 10/2025</u>**

1. वादी ने आदेश VI नियम 17 सीपीसी के तहत वादी द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पुनर्विलोकन हेतु इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

2. अनावश्यक विवरणों को काटते हुए, पुनर्विलोकन याचिका की ओर ले जाने वाले तथ्य यह हैं कि वादी ने नई दिल्ली की तहसील महरौली जिले के समालखा गांव के क्षेत्र में आयताकार / खसरा सं. 33/7/2, 33/8/2, 33/13, 33/14/1, 33/17, 33/118/2, 36/2 व 36/3 में शामिल लगभग 33 बीघा 09 बिस्वा भूमि के संबंध में दिनांक 16.09.1988 / 30.09.1988 के 13 विक्रय विलेखों की घोषणा और रद्द करने के आदेश हेतु वर्तमान वाद दायर किया है। वादी ने यह घोषणा करने की भी प्रार्थना की है कि प्रतिवादी का वादग्रस्त संपत्तियों पर अवैध कब्जा हैं।

3. यह वादी का मामला है कि वादी उक्त संपत्तियों का मालिक है। यह कहा गया है कि वर्ष 1986 में जसवंत सिंह भुल्लर ने अमेरिका में उनसे मुलाकात की थी और विशेष रूप से वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मद्देनजर वादी के हितों पर चिंता व्यक्त की थी। यह कहा गया था कि दिनांक 24.07.1987 को मुख्तारनामा वादी द्वारा तैयार किया गया था। यह वादी का मामला है कि दिनांक 24.07.1987 के मुख्तारनामा पर कभी कार्रवाई नहीं की गई और उसे वापस ले लिया गया।

4. यह कहा गया था कि उक्त जसवंत सिंह भुल्लर ने वादी को दीपक भारद्वाज से मिलवाया था। वादी को बताया गया कि दीपक भारद्वाज के पास भी उसी क्षेत्र में जमीन है और वह वादी की संपत्तियों की देखभाल करेगा। वादी इस बात से सहमत था कि उक्त दीपक भारद्वाज उसकी संपत्तियों की देखभाल कर सकता है। हालाँकि, दीपक भारद्वाज के पक्ष में वादी द्वारा कोई दस्तावेज़ निष्पादित नहीं किया गया था। यह कहा गया है कि वर्ष 2013 में कहीं, जब वादी भारत आया, तो उसे पता चला कि दीपक भारद्वाज की हत्या कर दी गई थी और उक्त दीपक भारद्वाज वादी की उक्त भूमि का दुरुपयोग कर रहा था। यह कहा गया है कि उक्त संपत्तियों के संबंध में कई विक्रय विलेख जसवंत सिंह भुल्लर द्वारा दिनांक 24.07.1987 के मुख्तारनामा के आधार पर निष्पादित किए गए थे, जिन पर कभी कार्रवाई नहीं की गई थी और जिन्हें वादी द्वारा वापस ले लिया गया था।

5. लिखित कथन में, एक विशिष्ट मामला उठाया गया है कि दिनांक 24.07.1987 के मुख्तारनामा को चुनौती दिए बिना, विरचित वाद सुनवाई योग्य नहीं है और इसे कब्जे के अनुतोष की अनुपस्थिति में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 द्वारा प्रभावित किया जाता है।

6. वादी ने आदेश VI नियम 17 सीपीसी के तहत एक आवेदन द्वारा दिनांक 24.07.1987 के मुख्तारनामा को निरस्त करने की मांग की। इस न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद उक्त आदेश द्वारा प्रार्थना को इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि प्रार्थना की परिसीमा समाप्त हो गई थी और चूंकि उपाय समाप्त हो गया था, इसलिए प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

7. इस न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 59 तथा प्रेम सिंह बनाम बीरबल, **(2006) 5 एससीसी 353** और एल. जे. लीच एंड कंपनी लिमिटेड बनाम जार्डिन स्किनर एंड कंपनी, **(1957) एससीसी ऑनलाइन एससी 68** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरोसा जताया है कि विक्रय विलेख वर्ष 1988 के हैं, शिकायत के कथन से पता चलता है कि वादी को वर्ष 2016 में धोखाधड़ी वाले विक्रय विलेखों के बारे में पता चला था, वाद वर्ष 2017 में दायर किया गया था और संशोधन की मांग की गई थी। वर्ष 2024 में दिनांक 24.07.1987 के मुख्तारनामा को निरस्त करने के लिए, जो इस आधार पर अनुमेय नहीं है कि

यदि कोई वाद उस तारीख को दायर किया गया था जब संशोधन की मांग की गई थी, तो वाद कालवार्जित हो गया था।

8. पुनर्विलोकन याचिका में वादी का मामला यह है कि यह न्यायालय परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 को ध्यान में रखने में विफल रहा है जो कब्जे के लिए वाद दायर करने के उद्देश्य से 12 साल का प्रावधान करता है जब कब्जा प्रतिवादी के प्रतिकूल हो गया था। प्रथम दृष्टया इस न्यायालय की राय है कि परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65 लागू नहीं होता है। यद्यपि वर्तमान मुकदमा कब्जे का वाद है, लेकिन जिस अनुरोध को पेश करने की मांग की गई थी, वह वादी को मुख्तारनामा की धोखाधड़ी के बारे में पता चलने के आठ साल बाद और वाद दायर करने के सात साल बाद धोखाधड़ी वाले मुख्तारनामा दिनांक 24.07.1987 को निरस्त करने हेतु था, जिसके बाद यह परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 के तहत समय के साथ प्रतिबंधित हो जाएगा।

9. किसी भी स्थिति में, इस न्यायालय की राय में, वादी द्वारा वांछित दलीलें पुनर्विलोकन याचिका के दायरे से बाहर हैं। यह स्थापित है कि पुनर्विलोकन का दायरा बेहद सीमित है और इसकी अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए जब अभिलेख में प्रत्यक्ष रूप से कोई त्रुटि स्पष्ट हो या कोई नया या महत्वपूर्ण साक्ष्य पाया जाए जो जानकारी में न हो और जो उचित परिश्रम

करने के बावजूद भी आदेश पारित करते समय इसे प्रदान नहीं कर पाया गया हो।

10. यह सुस्थापित है कि पुनर्विलोकन छद्म रूप में अपील नहीं हो सकती है। हरिदास दास बनाम उषा रानी बनिक, (2006) 4 एससीसी 78 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नवत अभिनिर्धारित किया:

> ***"13.*** *पुनर्विलोकन के दायरे को समझने हेतु, धारा 114 सीपीसी को पढ़ना होगा, लेकिन यह धरा न्यायालय से अपेक्षित हस्तक्षेप के दायरे को भी जोड़ती नहीं है क्योंकि यह केवल यह बताती है कि वह "उस पर ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे। "मानदंड आदेश 47 सीपीसी में निर्धारित किए गए हैं और इस वाद के उद्देश्यों के लिए, प्रतिवादी को "अभिलेखों में या किसी अन्य पर्याप्त कारण से स्पष्ट किसी अभाव या त्रुटि के कारण" फिर से सुनवाई के लिए दबाव डालने की अनुमति दें। नियम का पहला भाग आवेदक के लिए जिम्मेदार स्थिति से संबंधित है, और दूसरा एक न्यायिक कार्रवाई से संबंधित है जो स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है या जिस पर दो निष्कर्ष संभव नहीं हैं। उनमें से कोई भी विवाद की पुनः सुनवाई का अनुमान नहीं लगाता है क्योंकि एक पक्षकार ने मामले के सभी पहलुओं को उजागर नहीं किया था या शायद उन्हें अधिक बलपूर्वक तर्क दे सकता था और/या न्यायालय के लिए बाध्यकारी पूर्व निर्णय का हवाला दे सकता था और इस तरह एक अनुकूल निर्णय का आनंद ले सकता था। यह आदेश 47 के नियम 1 के स्पष्टीकरण से पूरी तरह से स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि यह तथ्य कि विधि के किसी प्रश्न पर निर्णय जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, किसी अन्य मामले में*

*उच्च न्यायालय के बाद के निर्णय द्वारा उलट या संशोधित किया गया है, ऐसा निर्णय पुनर्विलोकन के लिए आधार नहीं होगा। जहां विचाराधीन आदेश अपील योग्य है, पीड़ित पक्षकार के पास पर्याप्त और प्रभावी उपाय है और न्यायालय को अपने आदेश के पुनर्विलोकन करने की शक्ति का प्रयोग सबसे अधिक सावधानी के साथ करना चाहिए। यह न्यायालय तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश सरकार [(1964) 5 एससीआर 174:एआईआर 1964 एससी 1372] निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया:(एससीआर पृ. 186)*

> *"[न] यहाँ एक अंतर है जो वास्तविक है, हालांकि यह हमेशा व्याख्या करने में सक्षम नहीं हो सकता है, केवल एक त्रुटियुक्त निर्णय और एक निर्णय के बीच जिसे" स्पष्ट त्रुटि "द्वारा दुष्प्रभावित किया जा सकता है। एक पुनर्विलोकन किसी भी तरह से एक छद्म अपील नहीं है जिसमें एक त्रुटिपूर्ण निर्णय की फिर से सुनवाई और सुधार किया जाता है, लेकिन केवल पेटेंट त्रुटि के लिए निहित है।... जहाँ बिना किसी विस्तृत तर्क के कोई त्रुटि की ओर इशारा कर सकता है और कह सकता है कि यहां विधि का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो अत्यंत सुस्पष्ट है, और इसके बारे में उचित रूप से कोई दो राय नहीं हो सकती है, अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि का एक स्पष्ट मामला बनाया जाएगा।"*

11. इसी तरह, <u>मीरा भांजा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी,</u> **(1995) 1 एससीसी 170,** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-"

***8.*** *यह सुस्थापित है कि पुनर्विलोकन कार्यवाही अपील के माध्यम से नहीं होती है और इसे आदेश 47 नियम 1 सीपीसी के दायरे एवं परिधि तक सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए। आदेश 47 नियम 1 के तहत न्यायालय की शक्तियों की परिसीमा के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आदेशों के पुनर्विलोकन करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय को उपलब्ध समान अधिकारिता से निपटने के दौरान, यह न्यायालय, अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबम पिशाक शर्मा [(1979) 4 एससीसी 389:ए. आईआर 1979 एससी 1047] ने चिन्नाप्पा रेड्डी, न्या. के माध्यम से बोलते हुए, निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की हैं:*

> *'यह सत्य है कि संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है जो सम्पूर्ण अधिकारिता प्राप्त प्रत्येक न्यायालय में न्याय के उल्लंघन को रोकने या उसके द्वारा की गई गंभीर और स्पष्ट त्रुटियों को सुधारने के लिए निहित है। लेकिन, पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग की निश्चित सीमाएँ हैं। पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज पर किया जा सकता है, जो उचित परिश्रम के बाद पुनर्विलोकन की मांग करने वाले व्यक्ति के ज्ञान में नहीं था या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका जब आदेश पारित किया गया था; इसका प्रयोग किया जा सकता है जहां अभिलेख में कोई स्पष्ट गलती या त्रुटि पाई जाती है, इसका उपयोग किसी भी अनुरूप आधार पर भी किया जा सकता है। लेकिन, इसका प्रयोग इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि निर्णय*

> *गुणागुण के आधार पर त्रुटिपूर्ण था। वह अपील न्यायालय के अधिकाराधीन होगा। पुनरीक्षण की शक्ति को अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जो एक अपील न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सभी प्रकार की त्रुटियों को सुधारने में सक्षम बना सकती है।* " " (एससीसी पृष्ठ 172-73, पैरा 8)"

12. जैसा कि पहले कहा गया है, इस न्यायालय की राय में, वादी यह कथन करने का प्रयास कर रहा है कि न्यायालय परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के प्रभाव पर विचार करने में विफल रहा है जो पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर होगा। यह वादी का मामला नहीं है कि इस न्यायालय ने किसी ऐसे तथ्य पर भरोसा किया है जो अभिलेख में नहीं है या कि कोई नया तथ्य वादी की जानकारी में आया है या कोई भी ऐसे निर्णय जिस पर भरोसा जताया गया है, जिसे उलट दिया गया है और जिसके परिणामस्वरूप यह आदेश अनवधानता पूर्ण हो गया है। चूंकि वादी द्वारा यह तर्क देते हुए मामले पर फिर से तर्क देने का प्रयास किया गया है कि यह न्यायालय परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 पर विचार करने के प्रभाव पर विचार करने में विफल रहा है, इसलिए यह न्यायालय दिनांक 18.11.2024 आदेश की पुनर्विलोकन के लिए आवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

13. पुनर्विलोकन याचिका खारिज की जाती है।

**<u>अंतर.आ. 7989/2024 व अंतर.आ. 1955/2024</u>**

दिनांक 27.03.2025 को सूचीबद्ध किया जाए।

**न्या. सुभ्रमोणियम प्रसाद,**

**10 जनवरी, 2025**
एचएसके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*